आत्मनिर्भर भारत : गरीब कल्याण का भरोसा (Atamnirbhar Bharat : Reliance of Poor Welfare)

डॉ. सुमित्रा देवी शर्मा

Assistant Professor

प्रभा देवी मेमोरियल महाविद्यालय, जयपुर

लोक प्रशासन विषय में M.A., Ph.D., SET,

P.D.F. (ICSSR, New Delhi 2014-2016)

93, कैलाशपुरी, नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन

जगतपुरा, जयपुर (राज.) –302 017

सार

पूरा विश्व आज कोरोना वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों से संकट में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चुनौती की इस घड़ी को अवसर में बदलने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के साथ आगे बढ़ रहा है। 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि 'एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई हैं, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई हैं। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम्बकम् है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर उसे अवसरों में ढालना सीख लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके 'आत्मनिर्भर भारत' के अभ्युदय का नया सूरज उगाया है। अब तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केवल दो महीनों में गरीबों, मजदूरों, किसानों, विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में हस्तान्तरित किए जा चुके हैं। गरीबों के लिए पाँच महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है और मनरेगा के तहत 60 हजार करोड़ के बजटीय आवंटन के अलावा 40 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने इसके माध्यम से न केवल सुदृढ़ 'न्यू इंडिया' बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को भी साकार करने का खाका तैयार किया है। इसके माध्यम से भारत के भाल पर नव–निर्माण का सुनहरा भविष्य लिखा जाएगा।कोरोना संकट के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी और स्वावलम्बन का नारा देते हुए देश की आत्मा को जगाया है। साथ ही 'लोकल के लिए वोकल' कह कर स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की वकालत की है।कोरोना वायरस ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। दो गज की दूरी रखकर लोगों ने दुनिया को

इस बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया है ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि हमें कोरोना से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बनना है। कोरोना ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पंचायत, जिले, और राज्य आत्मनिर्भर बने, ताकि अपनी जरूरतों के लिए कभी बाहरियों का मुँह न देखना पड़े।

मुख्य शब्द : आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल, आर्थिक पैकेज, स्वावलम्बी भारत, वैश्विक महामारी, कोरोना, आपदा, क्रांतिकारी कदम, दिवालिया कार्यवाही, लॉकडाउन, अर्थव्यवस्था, स्थानीय उद्यम, गरीब कल्याण।

आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज[1]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश में कोरोना से उपजे आर्थिक संकट से देश को उभारने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया। इसमें पिछले दिनों घोषित राहत पैकेज भी शामिल हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण द्वारा चरणवार पैकेज का ब्योरा बताया गया है। पीएम ने कहा कि पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। पैकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ो लोगों की जीविका का साधन हैं। आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति और हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन–रात परिश्रम कर रहा है।

लोकल को बचाना हमारी जिम्मेदारी : प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, श्रमिक, प्रवासी मजदूर हों, मछुआरे हों, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में ऐलान होगा। कोरोना ने हमें लोकल मैन्यूफैक्चरिंग, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, लोकल मार्केटिंग का भी मतलब समझा दिया है। लोकल ने ही हमारी आपूर्ति की है और हमें बचाया है। लोकल जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।

किसका पैकेज कितना : भारत उन राष्ट्र की सूची में जिन्होंने जीडीपी का 10 प्रतिशत पैकेज के रूप में दिया है।

जापान	21.1%
अमरीका	13.0%
स्वीडन	12.0%
जर्मनी	10.7%
भारत	**10.0%**
फ्रांस	9.3%
स्पेन	7.3%
इटली	5.7%
ब्रिटेन	5.0%
चीन	3.8%

हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा : मोदी ने कहा, आज हर भारतवासी को लोकल के लिए 'वोकल' बनना है। न सिर्फ लोकल चीजें खरीदना है बल्कि उनका प्रचार भी करना है।

स्वावलम्बी भारत के पाँच पिलर...

1. इकोनॉमी : ऐसी इकोनॉमी जो इन्क्रीमेंटल चेंज नहीं, बल्कि क्वांटम जम्प लाए।
2. इन्फास्ट्रक्चर : एक ऐसी संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
3. सिस्टम : ऐसा सिस्टम जो 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था पर हो।
4. डेमोग्राफी : हमारी डेमोग्राफी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।
5. डिमांड : इस चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत[2]

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मई 2019 से मई 2020 तक के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 'एक राष्ट्र – एक कर', 'एक राष्ट्र – एक मोबिलिटी कार्ड', 'एक राष्ट्र – एक फास्ट टैग', 'एक देश – एक संविधान' और आज वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में 'एक राष्ट्र –एक राशन कार्ड' के कारण देश में राष्ट्रीयता की भावना आज अभूतपूर्व रूप से बलवती हुई है।

पूरा विश्व आज कोरोना वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों से संकट में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चुनौती की इस घड़ी को अवसर में बदलने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के साथ आगे बढ़ रहा है। 12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि 'एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई हैं, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई हैं। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम्बकम् है।

आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत[3]

भारत को विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाना, आतंकवाद के साए से देश को निकालकर उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार करना, स्वच्छता को हर भारतवासी का संस्कार बनाना, सच्चे अर्थों में गांव–गरीब–किसान का कायाकल्प करने का संकल्प और चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने की निपुणता तो भारत ने मोदी सरकार के पहले ही कार्यकाल में देख लिया था; दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष ने देश की जनता को सपनों के सच होने का यकीन भी दिला दिया।

जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए का उन्मूलन, श्रीराम मंदिर के निर्माण के मार्ग का प्रशस्तीकरण, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति और नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से आजादी के 70 सालों से वंचितों को उनका अधिकार देने जैसे कई कालजयी निर्णयों से एक ओर मोदी सरकार ने आजादी के बाद की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है तो वहीं दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' से देश के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इलाज के बोझ से मुक्ति दिलाने, करोड़ों गरीब महिलाओं का उज्ज्वला योजना के माध्यम से सशक्तीकरण, किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक कृषि सहायता राशि, हर गरीब को छत और हर नागरिक की जन–धन खातों के माध्यम से बैंकों तक पहुँच जैसे सर्वस्पर्शी निर्णयों के माध्यम से नए भारत का सृजन किया है। इस तरह मोदी सरकार सृजन और सुधार के समान्तर समन्वय की अभूतपूर्व मिसाल बनी है।

मोदी सरकार के द्वितीय संस्करण के प्रथम वर्ष में ऐसे कई एनिशियेटिव लिए गए जिससे वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली है जैसे कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एफडीआई का मार्ग प्रशस्त

कना, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, बैंकों का विलय, एनबीएफसी ऋण पर मोरोटोरियम, कम्पनी एक्ट में सुधार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए, आसान ऋण की व्यवस्था आदि। वर्षों से लम्बित ब्रू–रियांग शरणार्थी समस्या तथा बोडो समस्या का समाधान भी मोदी सरकार 2.0 के पहले साल में हुआ। दशकों से लम्बित चीप ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आरसीईपी का विरोध करके देश के किसानों एवं व्यवसायियों के हितों की सुरक्षा की गई जिसकी महत्ता कोरोना वायरस के मामले में चीन की भूमिका के मद्देनजर और बढ़ जाती है। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरीडोर बना कर न सिर्फ विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया बल्कि इससे लाखों–करोड़ की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई।

सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने वाली मोदी सरकार ने सामाजिक उत्थान को अपना मूल मंत्र बनाया। किसान, मजदूर एवं छोटे उद्यमियों के लिए पेंशन योजना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, एक देश – एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों की एमएसपी को डेढ़ गुना से अधिक करने का निर्णय, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स की विकास योजना, उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के साथ–साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति के आन्दोलन ने यह स्थापित किया कि गरीब कल्याण के सहारे भी जीडीपी ग्रोथ हासिल की जा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर उसे अवसरों में ढालना सीख लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके 'आत्मनिर्भर भारत' के अभ्युदय का नया सूरज उगाया है। अब तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केवल दो महीनों में गरीबों, मजदूरों, किसानों, विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में हस्तान्तरित किए जा चुके हैं। गरीबों के लिए पाँच महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है और मनरेगा के तहत 60 हजार करोड़ के बजटीय आवंटन के अलावा 40 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने इसके माध्यम से न केवल सुदृढ़ 'न्यू इंडिया' बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को भी साकार करने का खाका तैयार किया है। इसके माध्यम से भारत के भाल पर नव–निर्माण का सुनहरा भविष्य लिखा जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत की झलक भी बीते डेढ़ माह में दिख गई कि भारत किस तरह चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है। अप्रैल के शुरू में हम जहाँ पीपीई किट, वेंटिलेटर और एन–95 मास्क के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर थे, वहीं आज हम स्वयं बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। आज देश में प्रतिदिन लगभग 3.2 लाख पीपीई किट (अब तक एक करोड़ पीपीई किट भारत में बनाए गए हैं) और ढाई लाख एन–95 मास्क बनाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर का स्वदेशी संस्करण भी बाजार मूल्य से काफी कम कीमतों में देश के कई संस्थाओं ने तैयार कर लिया है। दस लाख से अधिक कोरोना बेड तैयार किए जा चुके हैं और हमने रोजाना डेढ़ लाख टेस्टिंग की क्षमता भी

हासिल कर ली है। संकट के समय हमने दुनिया के 55 से अधिक देशों को जरूरत की दवाइयों की आपूर्ति की है जिसकी सराहना दुनिया के सभी देशों ने की है। सही समय पर लॉकडाउन के चलते भारत ने कोरोना को काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है। कोरोना संकट के दौर में देश की अर्थव्यवसथा को सुचारू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी और स्वावलम्बन का नारा देते हुए देश की आत्मा को जगाया है। साथ ही 'लोकल के लिए वोकल' कह कर स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की वकालत की है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लगातार हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं जो भारत को सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाएगा।

देश को 'आत्मनिर्भरता सिखाएगी आपदा : मोदी[4]

'देश, कोरोना वायरस के संकट को अवसर के रूप में देख रहा है' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए 18 जून, 2020 को यह बात कही। उन्होंने कहा कि, ''यह आपदा देश को आत्मनिर्भर बनना और आयात पर निर्भरता को कम करना सिखाएगी।''

प्रधानमंत्री ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीलामी को एक बड़ा कदम बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र 'दशकों के लॉकडाउन से बाहर' आएगा। भारत में जितना कोयला भंडार है, लक्ष्य पहले स्थान का कोयला निर्यातक बनना होना चाहिए। इस नीलामी से अगले 5–7 वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जारी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की पाँचवीं किस्त जारी[5]

कोरोना और लॉकडाउन के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूँकने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण ने 17 मई, 2020 को गैर–रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर तमाम सरकारी कंपनियों के निजीकरण का रास्ता खोल दिया। 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए जारी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की पाँचवीं और आखिरी किस्त जारी करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि कंपनीज एक्ट के प्रावधानों में मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक जैसे कि सीएसआर रिपोर्टिंग या बोर्ड रिपोर्ट में छोटी–मोटी कमी रह जाने, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट होने, एजीएम में देरी आदि को आपराधिकरण की सूची से हटा दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों की संख्या आमतौर पर एक से चार ही होगी, अन्य का निजीकरण या विलय होगा या फिर उन्हें होल्डिंग कंपनी के अधीन लाया जाएगा।

कंपनी एक्ट : संशोधनों के लिए अध्यादेश : कंमनीज एक्ट के कम्पाउंडेबल ऑफेंस से संबंधित अधिकांश सेक्शन, इंटरनल अजूडकेशन मकेनिज्म (आइएएम) को स्थानांतरित होंगे। पहले आइएएम के अधीन 18 सेक्शन थे, वहीं अब इनकी संख्या 58 हो जाएगी। इन संशोधनों के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। सात कम्पांउडेबल ऑफेंस समाप्त कर दिए हैं।

दिवालिया कार्यवाही पर एक साल रोक : कोविड–19 से जुड़े ऋण इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आइबीसी) के तहत डिफॉल्ट में शामिल नहीं होंगे। एक साल तक कोई नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की न्यूनतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है।

मनरेगा : रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

300 करोड़ मानव दिवस काम के पैदा किए जा सकेंगे। मानसून के दौरान लौट रहे प्रवासी मजदूरों को इसकी ज्यादा जरूरत होगी।

मनरेगा में काम बढ़ाने से जल संरक्षण समेत रोजगार के टिकाऊ काम उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

इसके तहत अधिक से अधिक उत्पादन होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

आत्मनिर्भर पैकेज चरणवार

चरण–1	5,94,550 करोड़ रुपए
चरण–2	3,10,000 करोड़ रुपए
चरण–3	1,50,000 करोड़ रुपए
चरण–4 व 5	48,100 करोड़ रुपए
पहले घोषित	1,92,800 करोड़ रुपए
आरबीआइ उपाय	8,01,603 करोड़ रुपए
कुल	**20,97,053 करोड़ रुपए**

आत्मनिर्भर भारत की पाँचवीं किस्त में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस[6]

वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण ने आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज के पाँचवीं किस्त की घोषणा 17 मई, 2020 को की। पाँचवीं किस्त में सरकार द्वारा उठाए गए सात कदमों में मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा से सम्बन्धित, कारोबार और कोविड, कम्पनी एक्ट का गैर–अपराधीकरण, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य

सरकार के संसाधन को लेकर थे। इनमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके तहत पीएम ई–विद्या को तुरंत लॉन्च किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

लैब का नेटवर्क और ज्यादा होगा मजबूत : निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी जिला अस्पतालों में इंफेक्शन डीजीज ब्लॉक बनेगा। रूरल एरिया में अभी लैब नेटवर्क कमजोर है, इसे आगे मजबूर किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हेल्थ व वेलनेस सेंटर्स की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा।

स्कूलों के लिए होगा दीक्षा प्रोग्राम : इसके तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा प्रोग्राम होगा। इसमें सभी कक्षाओं के लिए ई–कंटेंट और क्यूआर कोड एनर्जाइज्ड यह वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉम होगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 12 के लिए प्रति क्लास एक चिन्हित टीवी चैनल होगा। जिसमें रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल होगा। दिव्यांगों के लिए भी विशेष ई–कंटेंट तैयार किया जाएगा, इसके तहत टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत के लिए 30 मई तक अनुमति दी जाएगी। वही पीएम ई–विद्या के अलावा मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यह छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के लिए होगा।

हेल्थ सेक्टर को 15,000 करोड़ : आत्मनिर्भर भारत के तहत हेल्थकेयर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण द्वारा 20 हेल्थकेयर के रिफॉर्म के लिए रोडमैप की जानकारी दी गई। वित्तमंत्री ने कहा कि हेल्थ सेक्टर पर आगे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में हेल्थ इंफास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा।

कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा : सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा का एलान किया है। साथ ही एपिडेमिक डीजीज एक्ट में भी सरकार ने बदलाव भी किया है।

इन मदों पर होगा खर्च :

- राज्य को जारी फंड 4113 करोड़
- एसेंशियल आइटस 3750 करोड़
- टेस्टिंग लैब और किट्स 550 करोड़

मास्क, पीपीई किट और दवाओं पर होगा खास फोकस

- पीपीई किट 51 लाख
- एन–95 मास्क 87 लाख
- एचसीक्यू टैबलेट्स 11.08 करोड़

अंतिम राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए क्रांतिकारी कदम[7]

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा हैं कि केन्द्र की ओर से घोषित अंतिम राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का उजाला पहुँचेगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि आर्थिक पैकेज से मजदूर, किसान, उद्यमी, आदिवासी सहित हर तबके को आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।

विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि केन्द्र सरकार की पीएम ई–विद्या योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल है, जो लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की अलख देश के घर–घर पहुँचाने में रामबाण साबित होगी।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि नरेगा के तहत 40 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिया है, इससे प्रवासियों को अपने घर में रोजगार मिलेगा। दो महीने का राशन देकर भी प्रवासियों को राहत दी गई है।

कोरोना वायरस ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। दो गज की दूरी रखकर लोगों ने दुनिया को इस बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया है ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि हमें कोरोना से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बनना है। कोरोना ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पंचायत, जिले, और राज्य आत्मनिर्भर बने, ताकि अपनी जरूरतों के लिए कभी बाहरियों का मुँह न देखना पड़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान पत्रिका, ''आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज'', जयपुर, राजस्थान, 13 मई, 2020, पृ. 1
2. राजस्थान पत्रिका, झा, प्रभात, ''अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है भारत'', जयपुर, राजस्थान, 28 मई, 2020, पृ. 8
3. राजस्थान पत्रिका, शाह, अमित, 'आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत'', जयपुर, राजस्थान, 30 मई, 2020,

पृ. 8

4. राजस्थान पत्रिका, ''देश को आत्मनिर्भरता सिखाएगी आपदा : मोदी'', जयपुर, राजस्थान, 19 जून, 2020, पृ. 13
5. राजस्थान पत्रिका, ''अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए उतारी निजीकरण की भागीरथी'', पैकेज की पाँचवीं और आखिरी किस्त जारी, जयपुर, राजस्थान, 18 मई, 2020, पृ. 1
6. राजस्थान पत्रिका, ''आत्मनिर्भर भारत की पाँचवीं किस्त में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस'', जयपुर, राजस्थान, 18 मई, 2020, पृ. 2
7. उपरोक्त, पृ. पत्रिका, सिटीजन

- राजस्थान पत्रिका, ''कोरोना का सबक आत्मनिर्भरता लड़ने का मंत्र दो गज की दूरी'', जयपुर, राजस्थान, 25 अप्रैल, 2020, पृ. 1